Entitlement Distribution Policy for 1991—93. After examining various suggestions, Government have made the following changes in the policy for the year 1992 and 1993:

(A) For 1992 and 1993, only quantities that become available from time to time on account of flexibilities and surrenders shall be allocated under the F.C.F.S. System.

(B) (i) The percentage of allocation under the Manufacturer-Exporter Entitlement (MEE) System has been raised from the present 18% to 20%.

(ii) The present limit of 125% on past performance allotments (PPE) and MEE allotments taken together in respect of MEE allotments has been removed.

(iii) The maximum number of country/category combination an exporter may opt under MEE System has been reduced from 15 to 10.

(C) Reservation of 75% Quota under Non-Quota Exporter Entitlement (NQE) system for thrust countries has been abolished. Base period under this system has been made at pqr with PPE System. The allocation in this system has been raised from the present 10% to 18% including 2% reservation exclusively for handloom garments.

गुजरात में कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

2607. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की वस्त्र नीति बन्द कपडा मिलों को पुन: खोलने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितनी मिलें बन्द हैं एवं कितने मजदूर इससे प्रभावित हुए हैं ;

(ग) सरकार ने गुजरात की बंद कपडा मिलों को पुन: चालू करने की दिशा में अब तक क्या उपाय किए हैं ; और

(घ) भविष्य में गुजरात में मिलें बन्द न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । (नीचे रखिये)

(ग) और (घ) सरकार द्वारा इन मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं : रूग्ण मिल की अर्थक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए नोडिए अभिकरण की स्थापना, आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करने के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना, पुनरुद्धार पैकेज बनाने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) की स्थापना ।

विवरण

बंद पड़ी सूती/मानव निर्मित वस्त्र मिलों की राज्यवार संख्या तथा उनमें प्रभावित कामगारों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	बंद पडी मिलों की संख्या	कामगार
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	2430
2.	बिहार	1	500
3.	गुजरात	31	55008
4.	हरियाणा	2	5292
5.	कर्नाटक	9	6907
6.	केरल	1	337
7.	मध्य प्रदेश	2	2636
8.	महराष्ट्र	11	21837
9.	राजस्थान	4	4841
10.	तमिलनाडू	21	17603
11.	उत्तर प्रदेश	8	17585
12.	पश्चिम बंगाल	9	17385
13.	दिल्ली	1	5161
		107	157522